भारत में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य

Ashish kumar

Motherhood University, Roorkee

सारांश

एक समान नागरिक संहिता इंगित करता है कि उनके धर्म से स्वतंत्र नागरिकों के लिए सामान्य सिद्धांतों या नागरिक नियमों की समान व्यवस्था की संभावना वे हिंदू, मुस्लिम या ईसाई हैं. यह नागरिकों के अधिकारों को उनके धर्म या जातीयता के आधार पर विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत शासित करता है. समान नागरिक संहिता में छुपा उद्देश्य धार्मिक विचारधाराओं के आधार पर विरोधाभासों को खत्म करना और राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा को बढ़ावा देना है ।

मानव अधिकार सभी मनुष्यों का एक पूर्ण मौलिक अधिकार है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, संस्कृति, परंपरा, लिंग कुछ भी हो। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) की प्रस्तावना "मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा और समान और अविच्छेद्य अधिकारों की मान्यता का प्रतीक है, जो दुनिया में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव है"। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 का अनुच्छेद 12 जो समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14), जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21), समान अवसर का अधिकार (अनुच्छेद 16) और संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के तहत शामिल कुछ अधिकारों जैसे कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता आदि के अधिकार में यूडीएचआर की अधिकांश घोषणाएं शामिल हैं। इस प्रकार, मानव अधिकारों का महत्व उपर्युक्त कानूनों से स्पष्ट है ।

भारत की धर्मनिरपेक्षतावादी प्रकृति को हमारे संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत किया गया है, जो भारत के नागरिकों को न्याय और समानता की गारंटी भी देता है। लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं के नाम पर, नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को न्याय और समानता से वंचित किया गया है। मसौदा तैयार करते समय संविधान तैयार करते समय अनैतिक प्रथाओं को मिटाने के लिए नागरिक संहिता को एकजुट करने का सुझाव दिया गया था, क्योंकि भारत के नश्वर धार्मिक विश्वासों से चिपके हुए थे, डीपीएसपी में समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) डाला गया था, जो इसके निहितार्थ के लिए राज्य पर कोई अनिवार्य शुल्क नहीं लगाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के महत्व को आधुनिक समय में समझा जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से स्पष्ट हैं जो पर्सनल लॉ में प्रचलित विवादों को हल करने और भारत के सभी नागरिकों के लिए बुनियादी मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता के निहितार्थ की सिफारिश करते हैं। समान नागरिक संहिता के पीछे मिथक यह है कि यह अल्पसंख्यक समुदायों पर बहुसंख्यकों की धार्मिक प्रथाओं को लागू कर सकता है, लेकिन वास्तविक अर्थों में समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विभिन्न समुदायों में प्रचलित अनैतिक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को खत्म करना और उन समुदायों के सभी सकारात्मक पहलुओं को एक संहिताबद्ध क़ानून के तहत लाना है।

कीवर्ड – मानवाधिकार, पर्सनल लॉ, समान नागरिक संहिता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक और समानता ।

परिचय:

एक यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड नागरिकों को उनके धर्म, स्थिति, और इसी तरह से स्वतंत्र के लिए सामान्य दिशानिर्देशों की समान व्यवस्था की संभावना का सुझाव देता है. सामान्य कानून गोद लेने, विवाह, उत्तराधिकार, विरासत आदि से संबंधित मामलों का प्रबंधन करता है. एक समान सामान्य कोड अंतर्निहित उद्देश्य धार्मिक विश्वास प्रणालियों के प्रकाश में विसंगतियों के निपटान द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के विचार की मदद करना है । साठ-सत्तर साल पहले, हम भारत के लोगों ने खुद को एक शानदार संविधान दिया — एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्र जहां न्याय, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व होगा. संविधान ने हमारे लिए कुछ मौलिक अधिकारों, और अदालतों के माध्यम से उन्हें लागू करने का अधिकार सुरक्षित किया. अन्य अधिकार जो तुरंत प्राप्त नहीं किए जा सकते थे, उन्हें अगले अध्याय में रखा गया, जिसे राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत के रूप में जाना जाता है. कानून की एकरूपता प्राप्त करने की दृष्टि से संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 को शामिल किया जो इस प्रकार है:

" राज्य सभी नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा "[1]

इस एकल पंक्ति से कई मुद्दे उठते हैं. वर्दी क्या करती है? नागरिक संहिता का मतलब यहाँ, हमारे पास पहले से ही एक समान आपराधिक कोड था — एक जो भारत के क्षेत्र में सभी पर लागू होता है. हमारे पास कई नागरिक कानून भी थे जो समान थे, जैसे अनुबंध अधिनियम, संपत्ति अधिनियम का हस्तांतरण, नागरिक प्रक्रिया संहिता, आदि. तो, इस समान नागरिक संहिता को वास्तव में पारिवारिक कानूनों के लिए संदर्भित किया जाता है, जिसे कभी-कभी व्यक्तिगत कानून भी कहा जाता है ।

स्वागत करने वाली भारतीय धरती पर विदेशियों के बसने, भारत के मूल निवासियों के साथ-साथ समृद्ध संसाधनों से आकर्षित अन्य देशवासियों के आक्रमण ने भारत को विभिन्न धर्मों का देश बना दिया है। यह वास्तव में एक भारतीय के लिए गर्व की बात है कि भारत संस्कृति, भाषा, धर्म, वस्त्र, विश्वास, परंपरा और संसाधनों में अपनी विविधताओं के बावजूद एकजुट खड़ा है ।अतीत से लेकर आज तक, धर्म ने अपने अनुयायियों द्वारा ईश्वर, निर्माता नामक सर्वोच्च शक्ति के विश्वास के साथ अपना महत्व प्राप्त किया है। धर्म भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। धर्म का प्रभाव पूजा शैली, दैनिक गतिविधियों, विवाह, अनुष्ठान और शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शित किया गया है ।

धर्म के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत कानूनों का अधिनियमन हुआ है। व्यक्तिगत कानून धर्मों की मान्यता और रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि की वैधता को नियंत्रित करते हैं। दुखद बात यह है कि कुछ लोगों के अधिकारों को अनुचित रूप से बढ़ाकर और दूसरों के अधिकारों को दबाकर असमानता उत्पन्न करने के लिए धर्म का दुरुपयोग किया गया है। जब दमित समुदाय द्वारा आवाज उठाई जाती है, तो उन्हें धर्म या धार्मिक विश्वास के नाम पर या तो धमकी दी जाती है या शांत किया जाता है।

संतृप्ति की बात तब होती है जब किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकार धर्म के मुखौटे के पीछे प्रभावित होते हैं। प्रकृति सभी के लिए अपरिवर्तित रहती है, चाहे मनुष्य किसी भी भगवान की पूजा करे। मानव शरीर, आंतरिक इंद्रियां, अधिकार सभी समान हैं, लिंग या धर्म की परवाह किए बिना। फिर भी धर्म के आधार पर बनाए गए पर्सनल लॉ में इंसानों के बीच भेदभाव होता है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा के वाद-विवाद में वास्तव में कहा है, "मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं समझ पा रहा हूं कि धर्म को इतना विशाल, विस्तृत अधिकार क्षेत्र क्यों दिया जाना चाहिए ताकि पूरे जीवन को कवर किया जा सके और उस क्षेत्र पर अतिक्रमण को रोका जा सके। न्यायिक अंग में धर्म को इतना व्यापक अवसर देना कि मानवाधिकारों के

[1] अनुसंधान विद्वान, डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ

उल्लंघन के मामले में भी उस पर सवाल न उठाया जा सके, किसी भी देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है, खासकर भारत जैसे देश के लिए जो सभी के लिए समानता और न्याय का लक्ष्य रखता है। इस प्रकार, समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, गोद लेने, रखरखाव और विरासत के क्षेत्रों में सभी भारतीयों के लिए एक आम कानून है, जो धार्मिक विश्वास का दुरुपयोग करके मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए एक स्थायी और बुद्धिमान समाधान हो सकता है।

समान नागरिक संहिता लागू करने का उद्देश्य और वस्तु:

समान नागरिक संहिता बनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण, एकता और अखंडता है और धर्मनिरपेक्षता इसकी मांग करती है। यह नए राष्ट्र-राज्य के संदर्भ में एकरूपता बनाम अल्पसंख्यक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता बनाम धार्मिक कानून और आधुनिकीकरण बनाम परंपरा के बारे में बहस बन गई। अनुच्छेद 44 का अंतिम उद्देश्य परिवार कानून में धर्मनिरपेक्षता है: 'एकरूपता का आह्वान केवल साधन है'। हाल के वर्षों में, यह मुद्दा महिलाओं के समूहों की बदलती स्थिति और इससे संबंधित कई मुद्दों पर तेज विभाजन के साथ काफी जटिल हो गया है [2]। इस तरह के कोड के पक्ष में बोलने वालों का मुख्य तर्क यह था कि इसमें भारत को एकजुट करने की क्षमता है क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों ने 1937 तक "सामान्य प्रथागत हिंदू नागरिक संहिता" का सुचारू रूप से पालन किया था जब "मुस्लिम लीग-ब्रिटिश गठबंधन" ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम[3] के माध्यम से मुसलमानों पर शरिया लगाकर उन्हें विभाजित किया था।

तो एकरूपता का क्या मतलब है? आज के संदर्भ में अनुच्छेद 44 में वर्दी शब्द का अर्थ समानता के अर्थ में समानता के रूप में लिया जाना चाहिए, समानता को आवश्यक रूप से एकल कोड द्वारा प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए। हमारे पास पहले से ही पारिवारिक मामलों के अलावा अन्य मामलों जैसे विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, रखरखाव, विरासत को अपनाने आदि में समान कानून हैं। यह वह क्षेत्र है जिसे एक समान या समान बनाया जाना है। अनुच्छेद 44 के तहत निहित एकरूपता या समानता की इस अवधारणा को न केवल अनुच्छेद 14 और 15 के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जो समानता के बारे में बात करता है, बल्कि अनुच्छेद 25 भी जो प्रदान करता है कि सभी व्यक्ति समान रूप से विवेक की स्वतंत्रता के हकदार हैं और धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार है[4] । अनुच्छेद 25 वास्तव में विभिन्न समुदायों को धर्म का अभ्यास करने की अनुमति देता है और इस प्रकार संयोग से उनके अलग-अलग व्यक्तिगत कानून हैं। अनुच्छेद 25 के तहत विभिन्न समुदायों को एक समान शब्द का उपयोग करके दिए गए अधिकार का अर्थ यह है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार समान रूप से उपलब्ध होगा और सभी के लिए लागू होगा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि यह एक कानून द्वारा किया जाना चाहिए, हालांकि यह आवश्यक नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने/अपने/धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता देता है, जिसमें उसके व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता शामिल है, पर्सनल लॉ उनके धर्म में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अधिकार की सीमा का उल्लेख डा अम्बेडकर ने हिन्दू संहिता विधेयक से संबंधित संसदीय बहस के दौरान स्पष्ट रूप से किया था। कई सदस्यों ने विधेयक को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह विवेकाधीन है। उन्होंने अनुच्छेद 25 का हवाला दिया और कहा कि किसी विशेष धर्म के पेशे में उस

---

[2] अनुच्छेद 44, भारत का संविधान, 1950।

[3] भारत में धर्म, नारीवादी राजनीति और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार, http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/Default.asp

[4] समान नागरिक संहिता: क्या यह भारत में काम करेगा, 2014। http://www.thehindu.com/opinion/open-page/uniform-civil-code-will-it-work-in-india/article6625409.ece (अंतिम बार देखा गया) मार्च 22, 2017)

व्यक्ति के स्वीय कानूनों का वहन होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संविधान विभिन्न समुदायों को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देता है और संयोग से उनका अपना कानून भी है, एक समुदाय को अपना कानून बनाने या इसे किसी भी तरह से संशोधित करने और दूसरे समुदाय के कानून को अलग तरीके से मानने या उसमें संशोधन करने की अनुमति देने में कुछ भी भेदभावपूर्ण नहीं है।

मानवाधिकारों का उल्लंघन:

मानवाधिकार सभी मनुष्यों के लिए उनकी संस्कृति, राष्ट्रीयता, धर्म, परंपरा, लिंग के बावजूद अविच्छेद्य मौलिक अधिकार हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवाधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता उभरी। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा और समान और अविच्छेद्य अधिकारों की मान्यता दुनिया में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव है"।[5] इसमें यह भी कहा गया है कि "मानवाधिकारों की अवहेलना और अवमानना के परिणामस्वरूप बर्बर कृत्य हुए हैं जिन्होंने मानव जाति की अंतरात्मा को अपमानित किया है, और एक ऐसी दुनिया का आगमन जिसमें मनुष्य भाषण और विश्वास की स्वतंत्रता का आनंद लेगा और भय और अभाव से स्वतंत्रता को आम लोगों की सर्वोच्च आकांक्षा के रूप में घोषित किया गया है।[6] भारत ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र, नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन की पुष्टि की है, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर कन्वेंशन और बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को भारत के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। इस प्रकार, "मानवाधिकारों को संवैधानिक मानवाधिकारों, कानूनी और नैतिक मानवाधिकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है।[7] भारत के संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकार जो यूडीएचआर की अधिकांश घोषणाओं को शामिल करते हैं, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, समान अवसर का अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल कुछ अन्य अधिकार समान कार्य के लिए समान वेतन, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। आम तौर पर, वे अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं लेकिन कुछ अधिकार जैसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसलिए समाज के सभी लोगों को बुनियादी मानवाधिकारों के महत्व की गारंटी दी जाती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना इस तरह से शुरू होती है, "हम, भारत के लोग, भारत को एक [संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य] बनाने और उसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प लेते हैं:

न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता;

स्थिति और अवसर की समानता;

और उन सभी के बीच प्रचार करने के लिए

व्यक्ति की गरिमा और [राष्ट्र की एकता और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता;

---

[5] मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, प्रस्तावना, 10 दिसंबर, 1948।

[6] उक्त।

[7] गोकुलेश शर्मा, मानवाधिकार और कानूनी उपचार, 147 (तीसरा संस्करण।

हमारी संविधान सभा में, नवम्बर, 1949 के इस छब्बीसवें दिन, एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और स्वयं को सौंपें।[8], जहां लोग अप्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट करते हैं कि भारत के सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं, चाहे उनका लिंग, जाति आदि कुछ भी हो, लेकिन धार्मिक प्रथाओं के नाम पर हमेशा मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, शायद समाज के कमजोर वर्ग विशेष रूप से यह महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है ।

नागरिक संहिता में एकरूपता:

भारत "विविधता में एकता" वाक्यांश के लिए जाना जाता है। देश विभिन्न धर्मों, संस्कृति, भाषा और व्यवसाय द्वारा विविध है। इस विविधता ने विभिन्न प्रथाओं और व्यक्तिगत कानूनों को जन्म दिया। लेकिन बाद में पर्सनल लॉ के नाम पर पुरुष वर्चस्व और अन्य भूलों को समाज में लाया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, "धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र"[9] जिसका अर्थ है कि "कोई राज्य धर्म नहीं है।[10] इसलिए, धर्म के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए ।

आशाजनक तथ्य यह है कि, मनुष्य अपने धर्म के बावजूद समान भावनाओं, अधिकारों के अधिकारी हैं और समान दर्द से पीड़ित हैं। लेकिन उपरोक्त तथ्य के विपरीत, विभिन्न धर्म अलग-अलग कानूनों का पालन करते हैं जो बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन में शामिल हैं। इस प्रकार, असमानता ने भारतीय धरती में अपनी जगह बनाई। जब हम लंबी धार्मिक बुराइयों पर करीब से नज़र डालते हैं, तो वे लिंग भेदभावपूर्ण प्रथाएं हैं ।

ब्रिटिश काल के दौरान भी, रूढ़िवादी लोगों के अस्तित्व के कारण सामान्य कानून नहीं लाए जा सके। लेकिन लोगों की यह मानसिकता संविधान निर्माण के समय भी बनी रही। इसके परिणामस्वरूप राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में समान नागरिक संहिता का समावेश हुआ क्योंकि वे कानून की अदालत द्वारा अप्रवर्तनीय हैं। संविधान के रूप में लिखा गया है "राज्य भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा"[11]। ये शब्द संविधान निर्माताओं की महान इच्छा को दर्शाते हैं कि वे अपने विश्वास और धर्म के बावजूद सभी भारतीयों के लिए एक समान नागरिक कानून लाएं, जो बदले में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। हालांकि इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया था, लेकिन राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें डर है कि वे अल्पसंख्यकों का वोट खो देंगे।

संविधान के निर्माताओं द्वारा एक समान नागरिक संहिता की इच्छा की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों के बुनियादी मौलिक अधिकार, उनकी धार्मिक और अन्य पहचान के बावजूद, एक बड़े मानवाधिकार ढांचे के भीतर संरक्षित हैं।[12] इस प्रकार, समान नागरिक संहिता उन महान दिमागों की भविष्यवाणी है जिन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था। एक समान नागरिक संहिता, जो समानता को बनाए रखकर नागरिकों के बीच एकता ला सकती है, अब तक एक सपना बना हुआ है ।

---

[8] भारत संविधान प्रस्तावना।

[9] भारत संविधान प्रस्तावना।

[10] समान नागरिक संहिता-समय के लिए एक आवश्यकता, शोधगंगा, http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/54472/11/11_ chapter%204.pdf

[11] इंडिया कॉन्स्टेंट अनुच्छेद 44.

[12] तुफैल अहमद, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मेरा ब्लूप्रिंट, डेलीओ, http://www.dailyo.in/politics/uniform-civilcode-Muslims-triple-talaq-Indian-constitution-supreme-court/story/1/14293.html।

समान नागरिक संहिता का अंतर्निहित सिद्धांत यह होना चाहिए कि संवैधानिक कानून एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में धार्मिक कानून को ओवरराइड करेगा।[13] लोगों की समानता के संवैधानिक अधिकार का अधिक्रमण करने वाले व्यक्तिगत कानून एक नकारात्मक संकेत है जो राष्ट्र के समग्र विकास के क्षरण का संकेत देता है। समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की धार्मिक प्रथाओं को लागू करने के लिए एक कदम नहीं है, यह सभी धर्मों में लिंग भेदभावपूर्ण बुराइयों को खत्म करने और उन्हें एक एकल कोड के तहत लाने के लिए एक कदम है जो समानता और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का उत्थान करता है ।

धार्मिक बुराइयाँ और न्यायपालिका का समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास:

न्यायपालिका ने इससे संबंधित शक्तियों के साथ, विभिन्न परिस्थितियों में अपने निर्णयों के माध्यम से देश और इसके सभी नागरिकों के कल्याण के लिए समान नागरिक संहिता लाने पर जोर दिया है। न्यायिक अंग कानून बनाने वाले अंग को विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और भरण-पोषण के लिए एक समान संहिता का मसौदा तैयार करने में आवश्यक कदम उठाने की सलाह देता रहा है।

ट्रिपल तालक, बहुविवाह, आदि मुस्लिम समुदाय में कुछ बुराइयाँ हैं क्योंकि मुस्लिम महिलाओं का अधिकार इन बुराइयों से पूरी तरह से वंचित है। समान नागरिक संहिता के महत्व को पहली बार ऐतिहासिक निर्णय "मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम"[14] में उजागर किया गया था, जिसे शाह बानो के मामले के रूप में जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "यह भी खेद का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र बना हुआ है[15] । मुस्लिम समुदाय के कई सदस्यों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मनोरंजन नहीं किया गया था और मुस्लिम अल्पसंख्यकों की मजबूरी से राज्य सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 में संशोधन किया, जिसने स्पष्ट रूप से मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव का दावा करने से वंचित कर दिया।

सरला मुद्गल बनाम भारत संघ[16] के मामले में कुलदीप सिंह जे ने कहा कि, "जब 80% से अधिक नागरिकों को पहले ही संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानून के तहत लाया जा चुका है, तो भारत के क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की शुरूआत को स्थगित रखने का कोई औचित्य नहीं है। एक समान फैसले में, आरएम सहाय, जे ने लिखा, "लेकिन धार्मिक प्रथाएं, मानवाधिकारों और गरिमा का उल्लंघन और अनिवार्य रूप से नागरिक और भौतिक स्वतंत्रता का पवित्र घुटन स्वायत्तता नहीं बल्कि उत्पीड़न है।[17]

---

[13] मोहित शर्मा, समान नागरिक संहिता को सार्वजनिक करना, लाइव लॉ, (16 अक्टूबर, 2016), http://www.livelaw.in/declassifying-uniform-civil-code/

[14] (1985) 2 एससीसी 556 (भारत)।

[15] समान नागरिक संहिता-समय की मांग, शोधगंगा, http://shodhnga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/54472/11/11_chapter%204.pdf।

[16] एआईआर 1995 एससी 1531

[17] रोनोजॉय सेन, आस्था-धर्म, धर्मनिरपेक्षता और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के लेख 144 (प्रथम संस्करण 2010)

अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप (AWAG) बनाम भारत संघ,[18] में मुस्लिम, हिंदू और ईसाई कानून में लिंग भेदभाव करने वाले प्रावधानों को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ में लैंगिक भेदभाव को हटाने के मामले में "राज्य पुलिस के मुद्दे शामिल हैं, जिनके साथ अदालत को आमतौर पर कोई चिंता नहीं होगी ।

ईसाई समुदाय में भी लैंगिक भेदभाव के प्रावधान हैं। उदाहरण के लिए, एक ईसाई व्यक्ति व्यभिचार के आधार पर अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है, लेकिन एक ईसाई महिला को तलाक प्राप्त करने के लिए परित्याग, क्रूरता जैसे कुछ अतिरिक्त आरोपों को साबित करना होगा। न्यायपालिका ने "स्वप्न घोष बनाम सदानंद घोष"[19] में लिंग भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खत्म करने के लिए प्रगतिशील कदम उठाए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10 और धारा 17 को असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। 1995 में, केरल उच्च न्यायालय ने "अम्मिनी ईजे बनाम भारत संघ"[20] में और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने "प्रगति वर्गीज बनाम सिरिल जॉर्ज वर्गीज"[21] में, भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10 को रद्द कर दिया क्योंकि वे लैंगिक समानता का उल्लंघन करते हैं ।

जॉन वल्लामट्टम बनाम भारत संघ[22] के मामले में सी.जे. खरे ने कहा कि, "हम यह बताना चाहेंगे कि अनुच्छेद 44 में प्रावधान है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह अत्यंत खेद का विषय है कि संविधान के अनुच्छेद 44 को प्रभावी नहीं बनाया गया है। देश में समान नागरिक संहिता बनाने के लिए संसद को अभी भी कदम उठाना बाकी है। समान नागरिक संहिता विचारधाराओं पर आधारित विरोधाभासों को दूर करके राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी।"

ऐतिहासिक मामले, सीमा बनाम अश्विनी कुमार[23], जिसने विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया, में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "अब समय आ गया है कि हम विवाह और तलाक के पंजीकरण पर केंद्रीय और राज्य कानूनों के संपूर्ण पहलू पर दोबारा गौर करें।" आकलन करें कि क्या सामाजिक विकास के इस चरण में देश में विवाह और तलाक पंजीकरण कानूनों की एक समान व्यवस्था संभव है और यदि नहीं, तो वर्तमान प्रणाली को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए क्या आवश्यक कानूनी सुधार किए जा सकते हैं।"

न्यायमूर्ति आरएम सहाय ने कहा है कि, "हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। धर्म की स्वतंत्रता हमारी संस्कृति का मूल है। जरा सा भी विचलन सामाजिक तंतु को हिला देता है। लेकिन धार्मिक प्रथाएं, मानवाधिकारों और गरिमा का उल्लंघन और आवश्यक नागरिक और भौतिक स्वतंत्रता का पवित्र घुटन स्वायत्तता नहीं बल्कि उत्पीड़न है। इसलिए, शोषितों की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत संहिता अनिवार्य है ।

---

[18] एआईआर 1997 एससी 3614 (भारत)।
[19] एआईआर 1989 कैल. 1 (भारत).
[20] एआईआर 1995 केर 252 (भारत)।
[21] एआईआर 1997 बीओएम 349 (भारत)
[22] 2003 (6) एससीसी 611 (भारत)।
[23] 2006 (2) एससीसी 578 (भारत)।

उपर्युक्त ऐतिहासिक निर्णयों से, यह स्पष्ट है कि बहुत सारी धार्मिक प्रथाएं हैं जो लिंग भेदभावपूर्ण हैं। उन प्रथाओं में न केवल अल्पसंख्यक समुदाय शामिल है बल्कि बहुसंख्यक समुदाय में भी शामिल हैं, यह बताया गया था कि दहेज हत्या के 90% मामले हिंदू समुदाय के हैं और शेष 10% अल्पसंख्यक समुदायों के मामले शामिल हैं। इस प्रकार, समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक समुदाय की प्रथाओं को लागू करने के लिए एक संहिता नहीं है।

सबसे अधिक बहस के विषय "समान नागरिक संहिता" का इस आधार पर विरोध किया गया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें बहुत सारी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाएं हैं और इसलिए समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से सांस्कृतिक पहचान मिट जाएगी।

भारत एक सभ्य और विकासशील राष्ट्र है, हालांकि संस्कृति और धर्म भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन संस्कृतियों और धार्मिक प्रथाओं को भारत के संविधान में नागरिकों को निहित बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में, हमारे पास अपराधों को विनियमित करने के लिए एक समान आपराधिक संहिता है और देश के सभी व्यक्तियों के लिए दंड समान हैं, चाहे उनका धर्म और लिंग कुछ भी हो। इसलिए, इसने व्यक्ति के अधिकारों को महत्व दिया, न कि धार्मिक प्रथाओं को। इसी तरह, एक समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में बुराइयों को खत्म करना और सभी धर्मों के लिए एक नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का लक्ष्य होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि यह सांस्कृतिक मानदंडों को मिटा देगा, इसका उद्देश्य केवल उन प्रथाओं और प्रावधानों को समाप्त करना है जो व्यक्तियों के बुनियादी मानवाधिकारों और वैधानिक और गैर-वैधानिक कानूनों का उल्लंघन करते हैं जो लिंग भेदभावपूर्ण हैं।

<u>समान नागरिक संहिता और न्यायपालिका की भूमिका</u>:

इस एकरूपता को प्रभावित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? अनुच्छेद के तहत राज्य शब्द सरकार की सभी शाखाओं अर्थात् विधायिका, कार्यकारी और न्यायपालिका को कवर करेगा। *श्रीमती जोहरा खातून बनाम मो.* इब्राहिम[24], कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रखरखाव भत्ते के आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि जब मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के विघटन के तहत महिला पक्ष से तलाक की कार्यवाही शुरू होती है, तो उन मामलों में पत्नी अपने पूर्व पति से न तो मुस्लिम कानून के तहत और न ही सीआरपीसी की धारा 125 के तहत रखरखाव का दावा नहीं कर सकती है। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उच्च न्यायालय का निर्णय इस आधार पर कि यह इस खंड के तहत धारा 125 के स्पष्टीकरण के खंड 1 (बी) की गलत व्याख्या पर आधारित है, पत्नी पत्नी बनी हुई है, भले ही वह तलाकशुदा हो, उसका पति या अन्यथा तलाक हो गया है और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।

सरला मुद्गल बनाम भारत संघ[25] के मामले में न्यायालय ने भारत सरकार को कानून और न्याय मंत्रालय के सचिव के माध्यम से इस न्यायालय में एक जिम्मेदार अधिकारी का हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें भारत के नागरिकों के लिए "समान नागरिक संहिता" हासिल करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और किए गए प्रयासों का

[24] एस0पी0 सठे. सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक के निहितार्थ. 1995; 3 (2): 2165-2166.
[25] एआईआर 1981 एससी 1243

उल्लेख किया गया है। *जॉन वल्लमेट्टन बनाम भारत संघ*[26] के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लागू न करने के लिए खेद व्यक्त किया।

यह निर्णय कार्यपालिका को समान नागरिक संहिता बनाने के लिए लगभग मजबूर करता प्रतीत होता है। अनुच्छेद 25 अपने आप में पर्सनल लॉ में वैधानिक संशोधन की अनुमति देता है। अनुच्छेद 25 (1) और 2 (बी) सामाजिक कल्याण और सुधार प्रदान करने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में किसी भी समुदाय के व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रदान करता है और साथ ही किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को प्रतिबंधित कर सकता है जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ी हो सकती है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है और धर्म का मामला अनुच्छेद 25 (2) के अधीन है। संविधान की 7 अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 केंद्र और राज्य दोनों को व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित संविधान के प्रारंभ से पहले सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने की अनुमति देती है।

यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (डीपी) में से एक है जो किसी भी अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत फिर भी देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा[27] निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देना है[28] । इसने मानवतावादी समाजवादी उपदेशों को निर्धारित किया जो भारतीय सामाजिक क्रांति के उद्देश्य थे। भाग III और IV अनिवार्य रूप से संविधान का एक मूल तत्व है जिसके बिना इसकी पहचान पूरी तरह से बदल जाएगी। हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच किसी भी असामंजस्य पर विचार नहीं किया। यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि निर्देशक सिद्धांत भाग लेने के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और मौलिक अधिकार ने उन साधनों को निर्धारित किया जिनके द्वारा लक्ष्य प्राप्त किया जाना था[29] । निर्देशक सिद्धांत राज्य के दायित्व हैं जिनकी पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य कार्रवाई को निर्देशित और व्याख्या की जानी चाहिए[30] ।

समान नागरिक संहिता की आवश्यकता एक सदी से भी अधिक समय से महसूस की जा रही है। एक देश के रूप में भारत पहले ही समान नागरिक संहिता के अभाव में बहुत कुछ झेल चुका है। धर्मों, संप्रदायों और सेक्स के नाम पर समाज को खंडित किया गया है। वर्तमान में भी, भारत में, व्यक्तिगत मामलों या विभिन्न समुदायों के लिए शादी, तलाक, रखरखाव, गोद लेने और विरासत जैसे कानूनों से संबंधित अधिकारों को नियंत्रित करने वाले अलग-अलग कानून हैं। इस प्रकार, हिंदुओं के बीच विरासत या तलाक को नियंत्रित करने वाले कानून मुसलमानों या ईसाइयों आदि से संबंधित कानूनों से बहुत अलग हैं। भारत में, अधिकांश परिवार कानून संबंधित पक्षों के धर्म द्वारा निर्धारित किए जाते हैं हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध हिंदू कानून के तहत आते हैं, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों के अपने कानून हैं। मुस्लिम कानून शरीयत पर आधारित है; अन्य सभी समुदायों में, कानूनों को भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा संहिताबद्ध किया जाता है। आपराधिक और नागरिक मामलों से निपटने के लिए कानूनों के अन्य सेट हैं, जैसे कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दंड संहिता, 1862। विविध जातियों

---

[26] एआईआर 1995 एससी 1531।
[27] एआईआर 2003 एससी 2902
[28] भारत का संविधान, अनुच्छेद. 37.
[29] केशवानंद भारती बनाम. केरल राज्य, एयर 1973 एससी 1461। वही
[30] डीएस नकारा बनाम भारत संघ, एआईआर 1983 एससी 130।

और पंथों और उनकी मान्यताओं या प्रथाओं के सेट विस्मयकारी रूप से भ्रमित करने वाले हैं और कहीं भी भारत की तरह एक परिदृश्य नहीं है, जिसमें विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को एक साथ रखने की अनुमति है।

एक समान नागरिक संहिता की मांग का अनिवार्य रूप से मतलब है कि इन सभी व्यक्तिगत कानूनों को एकजुट करना ताकि इन पहलुओं से निपटने वाले धर्मनिरपेक्ष कानूनों का एक सेट हो जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी समुदाय के हों। हालांकि इस तरह के एक समान कोड की सटीक रूपरेखा नहीं बताई गई है, लेकिन इसमें संभवतः सभी मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों के सबसे आधुनिक और प्रगतिशील पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए, जबकि उन लोगों को त्याग दिया जाना चाहिए जो प्रतिगामी हैं। भारत ने अपने सामने एक धर्मनिरपेक्ष समाज का आदर्श रखा है और इस संदर्भ में एक समान नागरिक संहिता की उपलब्धि अधिक वांछनीय हो जाती है। इस तरह की संहिता वैवाहिक कानूनों में विविधता को दूर करेगी, भारतीय कानूनी प्रणाली को सरल बनाएगी और भारतीय समाज को अधिक समरूप बनाएगी। यह कानून को धर्म से अलग कर देगा जो समाज के धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी पैटर्न में प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही वांछनीय उद्देश्य है[31] । यह एक राष्ट्रीय पहचान बनाएगा और देश में पृथकतावादी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। समान नागरिक संहिता में सभी के लिए लागू होने वाले समान प्रावधान होंगे और यह पारिवारिक मामलों में सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता पर आधारित होगा। भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति के अनुसार, "पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव को स्वीकार करने वाले विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को जारी रखना मौलिक अधिकारों और संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन करता है जो सभी नागरिकों को "स्थिति की समानता" सुरक्षित करने का वादा करता है, और प्राकृतिक एकीकरण की भावना के खिलाफ है। समिति ने समान नागरिक संहिता[32] को अपनाकर अनुच्छेद 44 में संवैधानिक निर्देश के शीघ्र कार्यान्वयन की सिफारिश की ।

मानवाधिकारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता: संवैधानिक गारंटी और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रसंविदाएं:

मानवाधिकार के दृष्टिकोण से व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों का अध्ययन करने की एक सम्मोहक आवश्यकता है। भारत ने समय-समय पर मानवाधिकारों की नियामक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का वचन दिया है, चाहे वह संविधान के प्रावधानों में हो या विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं और संधियों की शर्तों में। समानता, गैर-भेदभाव और निष्पक्षता के सिद्धांत जो मानवाधिकार प्रवचन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, भारत के व्यक्तिगत कानूनों के बारे में बहस का विषय हैं। ये सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में निहित हैं। लैंगिक समानता समानता का एक पहलू है और यह संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक है। इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रतिष्ठापित समानता का सिद्धांत कानून के समक्ष केवल औपचारिक समानता नहीं है, बल्कि वास्तविक और वास्तविक समानता की अवधारणा का प्रतीक है जो विशाल ऐतिहासिक, सामाजिक-आर्थिक और प्रथागत भेदभाव के कारण उत्पन्न होने वाली सभी असमानताओं पर प्रहार करता है। इस प्रकार, हम देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 (2) में कहा गया है कि धर्म की स्वतंत्रता

[31] लीला सेठ, एक समान नागरिक संहिता: लैंगिक न्याय की ओर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर क्वार्टरली, (स्प्रिंग), http://www.jstor.org/stable/2300597 पर उपलब्ध है। 2005; 31(4):40-54

[32] समानता की ओर: भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट (नई दिल्ली: भारत सरकार, सामाजिक और शैक्षिक कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण विभाग, संविधान सभा, 1974; 7:550।

के अधिकार के बावजूद सामाजिक सुधार और कल्याण प्रदान किया जा सकता है। अनुच्छेद 44 जो राज्य को अपने नागरिकों के लिए पूरे भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का निर्देश देता है, देश में महिलाओं की समानता के लिए आधारशिला है और इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए ताकि धार्मिक कानूनों के पुरातन भेदभावपूर्ण मानदंडों को खत्म किया जा सके।

महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW) एक अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें यह विशेष सूत्रीकरण की आवश्यकता पर आधारित था जो महिलाओं के मानवाधिकारों का दावा करेगा, उनकी रक्षा करेगा और उन्हें बढ़ावा देगा। कन्वेंशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित है और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को शामिल करता है, जिससे परिवार के अधिकार क्षेत्र को अपने दायरे में लाया जाता है। CEDAW की एक महत्वपूर्ण विशेषता निजी अभिनेताओं के कार्यों के लिए राज्य पर जिम्मेदारी तय करना है, खासकर जब इस तरह की कार्रवाई समुदाय के भीतर उल्लंघन का एक व्यवस्थित पैटर्न बनाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिंगभेद का सामाजिक-सांस्कृतिक आधार है और निजी अभिनेताओं द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है। भेदभाव के ऐसे पैटर्न में हस्तक्षेप करने के लिए राज्य की अनिच्छा उल्लंघनों की माफी होगी। CEDAW ने मानवाधिकार कानून और व्यवहार के लिए नए मानक स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन यह खेदजनक है कि CEDAW को आज सबसे आरक्षित मानवाधिकार सम्मेलन होने का गौरव प्राप्त है, यानी राज्य दलों ने आरक्षण खंडों के माध्यम से संधि के कुछ हिस्सों के संबंध में दायित्वों को संशोधित या माफ कर दिया है।

भारत ने भी समुदाय और परिवार के भीतर भेदभावपूर्ण सांस्कृतिक प्रथाओं को बदलने से संबंधित अपने दायित्वों को सीमित करने के लिए एक घोषणा के साथ CEDAW की पुष्टि की है। इसलिए, कन्वेंशन के लेखों 5 (ए) और 16 (1) के संबंध में, भारत घोषणा करता है कि "यह किसी भी समुदाय के व्यक्तिगत मामलों में अपनी पहल और सहमति के बिना हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति के अनुरूप इन प्रावधानों का पालन करेगा और सुनिश्चित करेगा"। भारत का आरक्षण प्रथागत प्रथाओं में राज्य के हस्तक्षेप से एक अयोग्य छूट है और यह एक समय सीमा निर्दिष्ट करने में भी विफल रहता है। इस आरक्षण को केवल कन्वेंशन के उद्देश्यों और उद्देश्य के साथ असंगत होने के रूप में माना जा सकता है और भारतीय राज्य की ओर से राजनीतिक इच्छाशक्ति की पूरी तरह से कमी का संकेत है, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय कर्तव्यों और दायित्वों के बावजूद, देश में एक समतावादी, समान नागरिक कानून लाने के लिए ।

मानवाधिकार और सुप्रीम कोर्ट:

वर्तमान मानवाधिकार प्रवचन की एक प्रमुख नारीवादी आलोचना यह है कि भेदभाव-विरोधी उपाय केवल सार्वजनिक अधिकारियों के आचरण के साथ खुद को चिंतित नहीं कर सकते हैं, अर्थात्, व्यक्तियों और सरकार के बीच संबंधों के साथ। घर, कार्यस्थल और स्कूल के 'निजी' क्षेत्र में भेदभाव को भी संबोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता में मध्यस्थता करने के लिए परिवार और समुदाय की संस्थाओं में निहित शक्ति है। देश की सर्वोच्च अदालत अक्सर इस झूठे सार्वजनिक-निजी द्वंद्व का शिकार हो गई है, जो निजी डोमेन को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप करने में विफल रही है ताकि उसमें भेदभावपूर्ण प्रथाओं की जांच की जा सके, शायद पारिवारिक मामलों आदि में बदलाव की आवश्यकता को 'सामाजिक' और 'विकासात्मक' मुद्दों के रूप में देखा जा सके। अधिकांश हस्तक्षेप टुकड़ों में किए गए हैं। ऐसे उदाहरणों में जहां अदालत पीड़ित पक्ष के प्रति सहानुभूति रखती है, उसने संबंधित धाराओं को व्यक्तिगत कानून

घोषित करने की आवश्यकता को इस तरह से पढ़कर और व्याख्या करके असंवैधानिक घोषित करने की आवश्यकता को दरकिनार कर दिया है कि किसी न किसी तरह, पीड़ित पक्ष को राहत प्रदान की जा सके।

इसके विपरीत, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र में भेदभाव को संबोधित करने में एक सराहनीय काम किया है और इस उद्देश्य के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं से संकेत लिया है। उदाहरण के लिए, इसने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के क्षेत्र में न्यायिक कानून बनाने के लिए कई दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। हालांकि, पर्सनल लॉ को अक्सर संसद में पर्सनल लॉ में भेदभाव को साफ करने का बोझ डालकर मौलिक अधिकारों की पहुंच से बाहर रखा गया है। आश्चर्य की बात है कि उच्चतम न्यायालय ने कतिपय अन्य निदेशों को पूरा प्रभाव देने में संकोच नहीं किया है

राज्य स्थान के सिद्धांत, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, और उन्हें मौलिक अधिकार की स्थिति में बढ़ाना। समान नागरिक संहिता लाने के संवैधानिक निर्देश पर एक समान दृष्टिकोण सामने नहीं आया है, हालांकि अदालतों ने समय-समय पर सरकार को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। हाल ही में फरवरी, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने विवाह योग्य उम्र और सहमति की उम्र में एकरूपता की कमी पर चर्चा करते हुए अल्पसंख्यक समुदायों के पर्सनल लॉ में आमूलचूल बदलाव करने में सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि यह उनकी धर्मनिरपेक्ष साख को दर्शाता है। विशेष रूप से, न्यायालय ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत कानूनों में सुधार के सरकार के प्रयास हिंदुओं से आगे नहीं बढ़े हैं जो इस तरह की पहल के प्रति अधिक सहिष्णु हैं। शायद शाह बानो प्रकरण ने पर्सनल लॉ में न्यायिक हस्तक्षेप की नीति में एक मील का पत्थर के रूप में कार्य किया। समुदाय की प्रतिक्रिया उतनी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं थी जितनी कि तत्कालीन सरकार द्वारा संवैधानिक निर्देशों, समतावादी मूल्यों और न्याय की धारणा की पूर्ण अवहेलना।

समान नागरिक संहिता के बारे में भ्रांति:

भारतीय संविधान के प्रारूपकारों के पास समानता की व्यापकता के साथ भारत के लोगों को नियंत्रित करने वाले सामान्य नागरिक कानून की दृष्टि थी। लेकिन उन महान दिमागों ने कभी नहीं सोचा होगा कि समान नागरिक संहिता गलत हाथों में संघर्ष कर रही है। आजकल, समान नागरिक संहिता का उपयोग राजनेताओं द्वारा उनके अनुचित खेल में एक उपकरण के रूप में किया जाता है। कुछ राजनेताओं ने एक मिथक बनाया है कि समान नागरिक संहिता, अल्पसंख्यकों को दबा देगी और उन पर बहुसंख्यक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को लागू करेगी। धार्मिक लोगों से वोट हासिल करने के स्वार्थी उद्देश्य पर राजनेताओं ने समान नागरिक संहिता के लिए बुरा चेहरा बनाया है और इसे सभी धार्मिक प्रथाओं और लोगों के विश्वास के खिलाफ चित्रित किया है। समान नागरिक संहिता की ऐसी गलत विचारधारा वर्तमान में समाज में व्याप्त है। वास्तविकता यह नहीं है कि सामान्य कानून सभी के लिए उनके धर्म के बावजूद समान कानून संहिता लाएगा। हमारे संविधान का मसौदा इतने त्रुटिहीन तरीके से तैयार किया गया है कि कानून सर्वोच्च विधान द्वारा अधिनियमित किए जाते हैं जिसे संसद कहा जाता है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। पारित किए जाने वाले विधेयक को अपने सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन और अंत में कार्यकारी प्राधिकरण की सहमति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, एक बिल एक अधिनियम बनने के लिए विभिन्न जांच से गुजरता है, इसलिए समान नागरिक संहिता कार्यान्वयन से पहले कई विश्लेषणों के अधीन होगी। ये विश्लेषण निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों की उपेक्षा नहीं करेंगे और बहुसंख्यक समुदाय को आँख बंद करके बनाए रखेंगे ।

समान नागरिक संहिता लागू करने के सुझाव:

नागरिकों को शिक्षित करना:

समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले, हमें भारत के नागरिकों को समान नागरिक संहिता की वास्तविक प्रकृति के बारे में शिक्षित करना चाहिए। जाति और धार्मिक विश्वास भारतीय नागरिकों के दिमाग से अविभाज्य हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता की वास्तविक प्रकृति और समाज पर इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में व्यक्तियों को शिक्षित करना समान नागरिक संहिता के सफल निहितार्थ का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह मीडिया समर्थन और सोशल मीडिया जागरूकता के माध्यम से किया जा सकता है।

Quandoaliquidprohibetur ex directo, prohibetur et per obliquum"-UCC का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए:

समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को दबाने का औजार नहीं बननी चाहिए। UCC का मुख्य उद्देश्य एक नागरिक संहिता लाना है जो सभी समुदायों पर लागू हो, चाहे उनका धर्म और लिंग कुछ भी हो; इसलिए, इसे बहुसंख्यक समुदाय के धार्मिक विचारों को अल्पसंख्यकों पर नहीं थोपना चाहिए। विधायिकाओं के निर्माताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि क्वांडोआलिक्विड निषेध पूर्व डायरेक्टो, निषेध एट प्रति ओब्लिकम, जिसका अर्थ है, "जब कुछ भी सीधे निषिद्ध होता है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से भी निषिद्ध होता है"[33]20। इसलिए, अल्पसंख्यकों को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए और उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

UCC को सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को नहीं मिटाना चाहिए:

भारत में विविध सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाएं हैं। और धर्म वह है जो प्रत्येक व्यक्ति के खून में दौड़ता है। इसलिए, UCC को सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि एक बार इसे लागू करने के बाद इसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो।

उदाहरण के लिए, ट्रिपल तलाक को अक्सर आवश्यक धार्मिक प्रथा के रूप में बहस की जाती है, लेकिन कुछ मुसलमानों को लगता है कि मनमाना तलाक एक स्वस्थ अभ्यास नहीं है और इसलिए इसे इस आधार पर निषिद्ध किया जा सकता है कि यह व्यक्तियों के बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है।

भारत के संविधान के धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार- संशोधन की आवश्यकता:

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25), धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26) केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए, किसी समुदाय को नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में युवाओं की आबादी अधिक है और वे तैयार हैं, व्यक्ति UCC के कार्यान्वयन के लिए तैयार हैं, फिर भी कुछ धार्मिक संगठन उनके विचार को दबा देते हैं और UCC के कार्यान्वयन को स्वीकार करने के लिए UCC का विरोध करते हैं।

[33] सुयशवर्मा, संवैधानिक कानून - रंगीन विधान का सिद्धांत और भारत का संविधान, QUORA, https://www.quora.com/What-could-be-the-limmitations-of-the-application-of-doctine-of-colorable-legislationin- अनुच्छेद-246 से संबंध.

समान नागरिक संहिता पर राजनीतिक प्रभाव में कमी:

कुछ राजनेता वोट बैंक की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी चुनाव लड़ने वाले दल या उम्मीदवार डरते हैं कि, समान नागरिक संहिता के लागू होने पर वे अल्पसंख्यकों और सामान्य संहिता के गैर-समर्थकों का वोट खो देंगे। यह डर अनावश्यक है क्योंकि सामान्य कोड व्यक्तियों को उनके आधारभूत अधिकार प्रदान करेगा जो सम्पूर्ण समाज द्वारा स्वीकार किए जाएंगे ।

निष्कर्ष:

धार्मिक प्रथाओं का शुद्ध रूप क्रूर दिमागों द्वारा कुछ अशुद्ध अपरंपरागत धार्मिक प्रथाओं में बदल गया है, ताकि समर्थित और दमित समूहों के बीच भेदभाव को चौड़ा किया जा सके। इस रूपांतरण ने व्यक्तिगत कानूनों को गहराई से प्रभावित किया है और मानवाधिकारों के उल्लंघन को जन्म दिया है जिसके परिणामस्वरूप सभी व्यक्तियों के लिए एक समान क़ानून की आवश्यकता है जो लिंग या धर्म में भेदभाव के बिना बुनियादी अधिकारों को बनाए रख सकते हैं। समान नागरिक संहिता की मांग ने समान नागरिक संहिता को अनुच्छेद 44 के तहत संविधान में पेश किए जाने के लगभग 68 वर्षों बाद आज भी बहस का विषय बना रखा है। समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से न्यायपालिका के लिए विवादों को निपटाने का काम बहुत आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि प्रत्येक धर्म के व्यक्तिगत कानूनों को देखने में समय लगेगा। यह बदले में सिविल संघर्षों से जुड़े मामलों के त्वरित परीक्षण में मदद करता है। समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए समय परिपक्व और वास्तव में खतरनाक है क्योंकि लोगों ने धार्मिक विश्वासों की तुलना में मानव गरिमा और मानवाधिकारों को उचित महत्व देना शुरू कर दिया है। समाज अब सभ्य हो गया है और स्वस्थ उत्थान की प्यास में है। इस प्रकार, इस उदाहरण पर नागरिक संहिता का कार्यान्वयन समानता सुनिश्चित कर सकता है और भारत के नागरिकों को ऐसा महसूस कराकर उन्हें बाध्य कर सकता है। पेपर के लेखकों को यकीन है कि वास्तविक विधायी कार्य के साथ समान नागरिक संहिता समाज द्वारा विशेष रूप से दमित समुदाय द्वारा और उन लोगों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त की जाएगी जो मानव के किसी भी उल्लंघन के बिना विकासशील भारत देखना चाहते हैं

पर्सनल लॉ के घूंघट के ठीक पीछे।

अभिव्यक्ति नागरिक संहिता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। एक नागरिक संहिता विवाह, तलाक, गोद लेने, बच्चों की अभिरक्षा, विरासत, संपत्ति के उत्तराधिकार आदि जैसे मामलों से संबंधित देश में नागरिकों के नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों और मूर्तियों का एक व्यवस्थित संग्रह है। वर्तमान संदर्भ में, इसका अर्थ है एक दूसरे के संबंध में नागरिकों के निजी अधिकारों से संबंधित कानून (मूल और साथ ही प्रक्रियात्मक) और इसे सार्वजनिक कानून से अलग किया जाना है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून या राजस्व कानून और यहां तक कि आपराधिक कानून, जहां पार्टियों में से एक राज्य है। डॉ. आंबेडकर ने इस तथ्य को समझाया, "नागरिक कानून की इन विभिन्न मदों में से अधिकांश को ब्रिटिश शासन के दौरान पहले ही संहिताबद्ध किया जा चुका है और एक समान संहिता के लिए अभी भी शेष एकमात्र प्रमुख आइटम विवाह, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार हैं" (गोद लेने और संरक्षकता) । यह ध्यान देने योग्य बात है कि विवाह, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार से संबंधित हिंदू संहिता के नाम पर स्वतंत्र होने के बाद से संसद द्वारा किए गए कई अधिनियम केवल हिंदुओं से संबंधित हैं जिनमें बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं और यह उन मुसलमानों को बाहर करता है जो भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के निर्माण पर अधिक आपत्ति जता रहे हैं। समान नागरिक संहिता मौलिक अधिकारों के संरक्षण और लोगों की धार्मिक विचारधारा के बीच सामंजस्य स्थापित करेगी ।